RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 333
दि. 06.04.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

दुनिया को महाशक्तियों की छाया से निकालने का मैक्रों का बड़ा आह्वान

पेरिस/सियोल। वैश्विक राजनीति के तेजी से बदलते परिदृश्य के बीच Emmanuel Macron ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अपने दौरे के दौरान मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया के देशों को अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के "जागीरदार" बनने से बचना चाहिए और एक स्वतंत्र, संतुलित तथा मूल्यों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक मंच पर अमेरिका की नीतियों को लेकर अनिश्चितता और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।

योनसेई विश्वविद्यालय में छात्रों और बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए मैक्रों ने दशकों पुरानी वैश्विक व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता दिखाई देती थी, लेकिन अब वही व्यवस्था लगातार उतार-चढ़ाव और अस्थिरता का सामना कर रही है। उनके अनुसार, वर्तमान वैश्विक माहौल में देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे खुद को किसी एक महाशक्ति के प्रभाव में समर्पित करने के बजाय अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया को अब केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक नई वैश्विक संरचना का निर्माण करना चाहिए।

मैक्रों का यह बयान सीधे तौर पर Donald Trump की नीतियों और हालिया बयानों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। हाल के दिनों में नाटो और पश्चिम एशिया को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। ट्रंप द्वारा नाटो को "कागजी शेर" कहे जाने और यूरोपीय सहयोगियों पर सवाल उठाने के बाद मैक्रों ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दिया कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा और कूटनीति को लेकर अधिक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सोच रहा है।

मैक्रों ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी एक शक्ति के अधीन होना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न तो वे चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करना चाहते हैं और न ही अमेरिका की नीतिगत

अनिश्चितताओं पर निर्भर रहना चाहते हैं। यह बयान उस बदलते वैश्विक संतुलन की ओर इशारा करता है, जहां मध्यम और उभरती शक्तियां अपनी स्वतंत्र भूमिका तय करना चाहती हैं। उन्होंने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों का उल्लेख करते हुए एक "स्वतंत्रता गठबंधन" बनाने का प्रस्ताव रखा, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित हो।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर भी मैक्रों ने अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि केवल सैन्य कार्रवाई या बमबारी के जरिए किसी भी जटिल संकट का समाधान संभव नहीं है। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका और इजरायल की नीतियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज है। मैक्रों ने संकेत दिया कि कूटनीतिक समाधान और बहुपक्षीय सहयोग ही स्थायी शांति का रास्ता हो सकता है।

इसी संदर्भ में United Nations Security Council में फ्रांस की भूमिका भी चर्चा में रही, जहां फ्रांस ने रूस और चीन के साथ मिलकर उस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसमें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देने की बात कही गई थी। इस कदम को मैक्रों की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे सैन्य टकराव के बजाय संवाद और संतुलन की नीति को प्राथमिकता दे रहे हैं।

हालांकि, मैक्रों केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने फ्रांस की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। मिसाइल, ड्रोन और पनडुब्बियों जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर उन्होंने यह संकेत दिया है कि फ्रांस अपनी सुरक्षा के मामले में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हाल ही में उन्होंने यह भी कहा था कि फ्रांस अपनी परमाणु सुरक्षा छतरी को जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों तक विस्तार देने पर विचार कर सकता है, जो यूरोप की सामूहिक सुरक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मैक्रों का यह बयान केवल एक राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। वे एक ऐसे विश्व की कल्पना कर रहे हैं जहां शक्ति संतुलन केवल दो महाशक्तियों के बीच सीमित न होकर, कई देशों के बीच संतुलित रूप से बंटा हो। यह विचार खास तौर पर उन देशों के लिए आकर्षक हो सकता है, जो अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव महसूस कर रहे हैं।

भारत जैसे देशों के लिए भी यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत लंबे समय से "रणनीतिक स्वायत्तता" की नीति का पालन करता रहा है। ऐसे में मैक्रों का "स्वतंत्रता गठबंधन" का विचार वैश्विक राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत कर सकता है, जहां समान विचारधारा वाले देश मिलकर एक संतुलित और न्यायसंगत व्यवस्था का निर्माण करें।

कुल मिलाकर, सियोल से दिया गया मैक्रों का यह संदेश केवल एक भाषण नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा का संकेत है। यह उस बदलते दौर की झलक है, जहां देश अपनी स्वतंत्र पहचान और हितों को प्राथमिकता देते हुए एक ऐसे विश्व की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो किसी एक शक्ति के प्रभुत्व से मुक्त हो। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मैक्रों की यह पहल कितनी सफल होती है और क्या वास्तव में दुनिया एक नई, संतुलित और बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ पाती है।

असम चुनाव 2026 में दागी उम्मीदवारों की मौजूदगी ने खड़े किए लोकतंत्र पर गंभीर सवाल

दिसपुर। असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक माहौल जहां एक ओर विकास, पहचान और क्षेत्रीय मुद्दों के इर्द-गिर्द घूम रहा है, वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर सामने आए आंकड़ों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। Association for Democratic Reforms की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस बार चुनावी मैदान में उतरे कुल 722 उम्मीदवारों में से 102 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। यह संख्या कुल उम्मीदवारों का लगभग 14 प्रतिशत है, जो यह दर्शाती है कि राजनीति में अपराधीकरण की समस्या अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन 102 उम्मीदवारों में से 82 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन गंभीर मामलों में हत्या, हत्या की साजिश, बल प्रयोग, उकसावे और अन्य संगीन आरोप शामिल हैं। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ऐसे उम्मीदवार न केवल चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि कई मामलों में प्रभावशाली राजनीतिक ताकत के रूप में उभरते भी दिखाई देते हैं।

अगर पिछले विधानसभा चुनाव 2021 से तुलना की जाए, तो इस बार स्थिति में मामूली सुधार जरूर देखने को मिला है। 2021 में कुल 941 उम्मीदवारों में से 138 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जो लगभग 15 प्रतिशत के बराबर था। इस बार यह आंकड़ा घटकर 14 प्रतिशत पर आ गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार बहुत सीमित है और इसे बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब भी हर सात में से एक उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। All India United Democratic Front के 20 उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो लगभग 37 प्रतिशत है। यह सभी प्रमुख दलों में सबसे अधिक है। इसके बाद Indian National Congress का स्थान आता है, जिसके 99 उम्मीदवारों में से 28 उम्मीदवार (करीब 28 प्रतिशत) आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। Asom Gana Parishad के 26 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवारों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

वहीं, Bharatiya Janata Party के उम्मीदवारों में यह प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, जहां करीब 9 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। हालांकि, यह भी इस बात का संकेत है कि कोई भी राजनीतिक दल इस समस्या से पूरी तरह अछूता नहीं है।

व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ मामलों की संख्या काफी अधिक है। Akhil Gogoi के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें साजिश और उकसावे जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। Badruddin Ajmal ने अपने हलफनामे में एक आपराधिक मामले का जिक्र किया है, जबकि Shiladitya Dev के खिलाफ करीब 13 मामले दर्ज बताए गए हैं। दूसरी ओर, असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने अपने हलफनामे में किसी भी आपराधिक मामले के लंबित न होने की जानकारी दी है।

इन आंकड़ों ने एक बार फिर उस बहस को तेज कर दिया है कि क्या भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। चुनाव आयोग द्वारा सख्त नियम बनाए जाने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, राजनीतिक दल अक्सर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनकी जीत की संभावना अधिक होती है, भले ही उनके खिलाफ गंभीर आरोप क्यों न हों। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ मानी जाती है, क्योंकि इससे साफ-सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाती है।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मतदाताओं की भूमिका इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक जनता ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना बंद नहीं करती, तब तक राजनीतिक दलों पर दबाव नहीं बनेगा कि वे साफ छवि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, ताकि वे केवल जीत की संभावना के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण करें।

असम जैसे राज्य में, जहां सामाजिक और जातीय विविधता के साथ-साथ विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, वहां चुनावी प्रक्रिया का साफ और पारदर्शी होना बेहद जरूरी है। ऐसे में दागी उम्मीदवारों की बड़ी संख्या लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर असर डाल सकती है।

कुल मिलाकर, असम चुनाव 2026 के ये आंकड़े यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि भले ही कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन राजनीति में अपराधीकरण की समस्या अब भी जड़ें जमाए हुए है। यह केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चुनौती है, जिसे दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनी सख्ती और जागरूक मतदाता—तीनों की जरूरत है। आने वाले चुनाव परिणाम यह तय करेंगे कि क्या मतदाता इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं या फिर यह समस्या यूं ही बनी रहती है।

बंगाल की सियासत में गरमाया माहौल बीजेपी ने ठोकी सत्ता की दावेदारी

झारग्राम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और इसी बीच Dharmendra Pradhan ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस बार राज्य में Bharatiya Janata Party पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने सत्तारूढ़ All India Trinamool Congress पर तीखा हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और दमनकारी शासन के आरोप लगाए, जिससे राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।

झारग्राम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि इस बार चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि जनता खुद मैदान में उतर चुकी है। उनके अनुसार, बंगाल की जनता अब बदलाव के मूड में है और वह भ्रष्टाचार तथा भय के माहौल से मुक्ति चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य में लंबे समय से जो राजनीतिक संस्कृति बनी हुई है, उसमें आम लोगों की आवाज दबाई गई है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और जनता निर्णायक फैसला लेने के लिए तैयार है।

प्रधान ने विपक्ष के उस आरोप पर भी जवाब दिया, जिसमें भाजपा नेताओं को "बाहरी"

बताया जाता रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि Suvendu Adhikari, Samik Bhattacharya और Dilip Ghosh जैसे नेता क्या बाहरी हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी नेता बंगाल की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा अब बंगाल में जमीनी स्तर पर मजबूत हो चुकी है।

केंद्रीय मंत्री ने Mamata Banerjee सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मालदा में हाल ही में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य में बिगड़ती स्थिति का उदाहरण है। उनके अनुसार, कानून-व्यवस्था का लगातार कमजोर होना इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक नियंत्रण ढीला पड़ चुका है और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

प्रधान ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल धीरे-धीरे संवैधानिक नियंत्रण से बाहर जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के पास सुशासन के लिए कोई स्पष्ट नीति या एजेंडा नहीं है और शासन का तरीका डर और दबाव पर आधारित हो गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की कार्यशैली स्वीकार्य नहीं हो सकती और इसे बदलना जरूरी है। भाजपा की रणनीति पर बात करते हुए प्रधान ने "डबल इंजन सरकार" का जिक्र किया। उनका कहना था कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक दशक में भाजपा ने बंगाल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और अब वह एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर चुकी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा सत्ता में आने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। चुनाव से पहले इस तरह के बयान राजनीतिक माहौल को और गरमा रहे हैं और यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा।

कुल मिलाकर, बंगाल की सियासत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां हर दल अपनी-अपनी रणनीति के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है और क्या वास्तव में राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है या फिर मौजूदा सरकार अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहती है।

चीन-ईरान गठजोड़ से बढ़ा पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक नई रणनीतिक हलचल ने वैश्विक चिंताओं को और गहरा कर दिया है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार China की मदद से Iran तेजी से अपनी मिसाइल क्षमता को फिर से मजबूत कर रहा है, जिससे United States और Israel के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब क्षेत्र पहले ही सैन्य टकराव और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है।

Institute for the Study of War की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई महत्वपूर्ण मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों में ईंधन उत्पादन इकाइयों, सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट, स्टोरेज सुविधाओं और मिसाइल निर्माण केंद्रों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की आक्रामक सैन्य क्षमता को कमजोर करना था, ताकि क्षेत्र में उसकी रणनीतिक ताकत को सीमित किया जा सके।

लेकिन इन हमलों का असर अपेक्षा से कम होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की ओर से मिल रही तकनीकी और सामग्री सहायता के कारण ईरान ने अपनी क्षतिग्रस्त क्षमताओं को बहुत तेजी से पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर सॉलिड मिसाइल ईंधन बनाने में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण रसायनों की आपूर्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद से चीन ने कम से कम पांच बार सोडियम पर्क्लोरेट जैसे केमिकल ईरान को भेजे हैं। यह रसायन सॉलिड रॉकेट फ्यूल के निर्माण में बेहद अहम माना जाता है। इन सामग्रियों की आपूर्ति Islamic Republic of Iran Shipping Lines से जुड़े जहाजों के जरिए की गई, जो पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में हैं। मरीन ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, ये जहाज चाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास जैसे रणनीतिक स्थानों के पास देखे गए, जहां से इन सामग्रियों को आगे मिसाइल ठिकानों तक पहुंचाया गया।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन की इस सहायता ने ईरान को न केवल अपने मिसाइल नेटवर्क को तेजी से पुनर्स्थापित करने में मदद की है, बल्कि हमलों के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्षमता को भी मजबूत किया है। कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया था, वे कुछ ही घंटों में फिर से सक्रिय हो गए। इससे यह संकेत मिलता है कि ईरान का सैन्य ढांचा बेहद लचीला और बहुस्तरीय है, जिसे पूरी तरह निष्क्रिय करना आसान नहीं है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का मिसाइल नेटवर्क केवल लॉन्चिंग साइट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सप्लाई चेन, स्टोरेज, मोबाइल लॉन्च सिस्टम और बैकअप सुविधाएं भी शामिल हैं। यही कारण है कि एक या दो हमलों से इसकी पूरी क्षमता को खत्म करना संभव नहीं होता। चीन की ओर से मिल रही मदद इस नेटवर्क को और अधिक टिकाऊ बना रही है।

इस घटनाक्रम ने अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब उन्हें न केवल ईरान की सैन्य ताकत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसके पीछे खड़े वैश्विक समर्थन को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। यह स्थिति एक व्यापक भू-राजनीतिक संघर्ष का संकेत देती है, जहां क्षेत्रीय युद्ध धीरे-धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बनता जा रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, यदि चीन और ईरान के बीच यह सहयोग इसी तरह जारी रहा, तो यह मौजूदा संघर्ष में "गेम-चेंजर" साबित हो सकता है। इससे न केवल पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई शक्ति संरचना उभर सकती है। खास तौर पर उन देशों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो पहले से ही अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आर्थिक और रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। चीन, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों के लिहाज से ईरान को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, जबकि ईरान को वैश्विक दबाव के बीच एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है। ऐसे में दोनों देशों का यह गठजोड़ आने वाले समय में और मजबूत हो सकता है।

कुल मिलाकर, पश्चिम एशिया की यह स्थिति अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा तय करने वाली एक बड़ी कहानी बनती जा रही है। चीन की बढ़ती भूमिका, ईरान की पुनर्स्थापित होती सैन्य क्षमता और अमेरिका-इजराइल की रणनीतिक चुनौतियां मिलकर एक ऐसे दौर की ओर इशारा कर रही हैं, जहां हर कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या कूटनीति इस बढ़ते तनाव को कम कर पाती है या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ती है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

कमाई की कहानियां और जिम्मेदारी का सवाल

सिनेमा की दुनिया जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे उतनी ही जटिल बहसें भी चलती रहती हैं। जब कोई फिल्म अचानक से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर लेती है, तो उसकी सफलता केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उससे जुड़े नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न भी सतह पर आने लगते हैं। हाल के समय में एक ऐसी ही बहस ने जन्म लिया है, जिसमें यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी खास समुदाय या इलाके की कहानी दिखाकर कमाई करने वालों पर उस समुदाय के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं। जब कोई फिल्म किसी विशेष स्थान या समाज की वास्तविकताओं को आधार बनाकर बनाई जाती है और उससे भारी मुनाफा होता है, तो स्वाभाविक रूप से उस स्थान के लोग यह सोचने लगते हैं कि उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष और उनकी पहचान का इस्तेमाल करके यह सफलता हासिल की गई है। ऐसे में वे अपने हिस्से की मांग करें, तो इसे पूरी तरह अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। यह मांग केवल पैसों की नहीं होती, बल्कि उस पहचान और योगदान को स्वीकार करने की भी होती है, जिसे फिल्म ने अपने कथानक का हिस्सा बनाया। लेकिन इस पूरे मुद्दे का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिल्म निर्माण एक जोखिम भरा व्यवसाय है, जहां करोड़ों रुपये दांव पर लगाए जाते हैं। निर्माता और निर्देशक यह तर्क देते हैं कि उन्होंने किसी सामाजिक सेवा के उद्देश्य से फिल्म नहीं बनाई, बल्कि यह उनका पेशा है। अगर फिल्म असफल होती है, तो नुकसान भी वही उठाते हैं। ऐसे में जब फिल्म सफल होती है, तो उसके लाभ पर भी उनका ही अधिकार होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी समुदाय को कमाई का हिस्सा देने की बाध्यता तय करना एक कठिन और विवादास्पद मुद्दा बन जाता है। फिर भी, जब फिल्मों का विषय संवेदनशील होता है—जैसे किसी समुदाय की पीड़ा, ऐतिहासिक घटनाएं या सामाजिक अन्याय—तब यह बहस और गहरी हो जाती है। दर्शक जब ऐसी फिल्मों को देखते हैं, तो वे केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव से गुजरते हैं। वे उस दर्द को महसूस करते हैं, जिससे फिल्म के पात्र गुजरते हैं। यही कारण है कि कई लोग यह मानते हैं कि अगर किसी की पीड़ा को दिखाकर पैसा कमाया जा रहा है, तो उस पीड़ा को कम करने के लिए भी कुछ प्रयास होने चाहिए। यहां एक दिलचस्प विरोधाभास भी देखने को मिलता है। समाज में अक्सर संवेदनाएं चयनात्मक होती हैं। कुछ मुद्दों को लेकर लोग बेहद सक्रिय हो जाते हैं, जबकि अन्य मुद्दों को उतनी ही आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। यही प्रवृत्ति फिल्मों के मामले में भी दिखाई देती है। कुछ फिल्मों को लेकर भावनात्मक बहस छिड़ जाती है, जबकि कुछ अन्य फिल्मों को कोई विशेष ध्यान नहीं मिलता, चाहे उनका विषय कितना ही गंभीर क्यों न हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि दर्शकों की सोच और उनकी प्राथमिकताएं भी इस पूरे खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। असल में, यह पूरा विवाद केवल फिल्मों या फिल्मकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। हम अक्सर उन कहानियों को ज्यादा महत्व देते हैं, जो हमारे विचारों या भावनाओं से मेल खाती हैं। जो कहानियां हमारे नजरिए से अलग होती हैं, उन्हें हम उतनी गंभीरता से नहीं लेते। यही कारण है कि कुछ विषयों पर बनी फिल्में जबरदस्त सफलता हासिल कर लेती हैं, जबकि अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विषयों पर बनी फिल्में दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पातीं।

इस संदर्भ में यह सवाल भी उठता है कि क्या सिनेमा को केवल एक व्यवसाय के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। अगर सिनेमा केवल कमाई का जरिया बनकर रह जाएगा, तो वह अपनी उस शक्ति को खो देगा, जिसके जरिए वह समाज में बदलाव ला सकता है। वहीं अगर फिल्मकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करें, तो वे न केवल मनोरंजन कर सकते हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं।

घरवाली-बाहरवाली का त्रास झेलती स्त्री

> “ जो माता-पिता न जाने कितने संसाधन लगाकर अपनी बेटियों को पालते हैं, उन्हें पढ़ाते, लिखाते हैं, उनका विवाह करते हैं, उनकी अच्छी गृहस्थी के सपने देखते हैं, यदि वही लड़की इस तरह से जीवन के थपेड़ों को सहने के लिए पति और कानून द्वारा अकेली छोड़ दी जाएगी, तो इन माता-पिता का क्या होगा।

हाल ही में प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा पुरुष, किसी अन्य महिला के साथ लिव-इन में रह सकता है। इस तरह रहना कोई अपराध नहीं है। नैतिकता और कानून को अलग रखना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आदमी से तलाक और मुआवजा ले सकती है। जबकि प्रयागराज हाईकोर्ट की एक दूसरी बैंच ने निर्णय दिया कि वे उन लिव-इन जोड़ों को सुरक्षा नहीं दे सकते, जो पहले से ही शादीशुदा हैं और जिन्होंने तलाक नहीं लिया है। ऐसे जोड़ों के जीवन में दखल देने का अधिकार भी किसी को नहीं है। लेकिन इसे कानूनी मान्यता तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि तलाक न हो। वास्तव में, परम स्वतंत्रता जैसी चीज कोई नहीं होती। हां, यदि ऐसे जोड़ों को किसी हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वे पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हैं।

इसी तरह का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिया था। अदालत ने कहा था कि दो वयस्क अपनी मर्जी से साथी चुन सकते हैं। और साथ रहने का फैसला कर सकते हैं। इन्हें यदि अपने परिवार के लोगों से खतरा है, तो पुलिस सुरक्षा लेने का पूरा अधिकार है।

कानून को देखें तो बिना तलाक लिए इस तरह रहने की इजाजत नहीं होती। इसके अलावा बहुत-सी अदालतों ने इसे पति या पत्नी के अधिकारों का उल्लंघन भी माना है। एक जमाने में भारत में बदचलनी (एडल्टरी) को कानूनन अपराध माना जाता था, लेकिन अब वह अपराध नहीं है। लेकिन इसके आधार पर तलाक मिल सकता है। अक्सर बहुत से सामाजिक मुद्दे कानूनी दांव-पेच में खो जाते हैं।

बहुत से पुरुषों की सोच रहती है कि घर में एक पत्नी है, जो उनके परिवार की जरूरतों और बच्चों के पालन-पोषण के लिए है, लेकिन बाहर घूमने-फिरने, मौज उड़ाने के लिए एक और स्त्री चाहिए। घरवाली बाहरवाली, जैसी फिल्में विगत में सुपरहिट होती रही हैं। मशहूर हिंदी लेखक स्व. जैनेंद्र कुमार ने तो सत्तर के दशक में एक प्रस्थापना ही दे डाली थी कि लेखकों को प्रेरणा पाने के लिए पत्नी के अलावा एक प्रेमिका भी चाहिए। उस समय जैनेंद्र जी के इस कथन पर बहुत विवाद भी हुआ था। कई स्त्रियों ने कहा था कि यदि पत्नियां भी ऐसा ही कहने लगें कि उन्हें भी लिखने के लिए पति के अलावा एक और प्रेमी चाहिए, तो क्या होगा।

यह भी सच है कि दबे-छिपे ऐसा होता भी रहता है। बहुत-सी जगह कानून एक तरफ चलता है, और समाज के दवाब दूसरी तरफ। अब भी कई कम्युनिटीज ऐसी हैं, जहां पुरुष कई विवाह कर लेते हैं। कई जगहों पर स्त्रियों को भी यह सुविधा प्राप्त है। यदि हालिया निर्णय के संदर्भ में पढ़ें, शादीशुदा पुरुषों को कानून का सहारा भी मिल जाएगा कि वे किसी और के साथ रह सकें। जो स्त्री किसी की पत्नी है, उसे हमेशा यह डर सताता रहेगा कि कहीं उसका पति किसी और के साथ रहने चला गया, तो उसका क्या होगा। हर स्त्री के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वह ऐसे मामले में अदालतों के चक्कर लगा सके और न्याय प्राप्त कर सके। यदि इस स्त्री के बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा। पति तो किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया होगा। और क्या मात्र तलाक मिलने या मुआवजा मिलने से इस तरह से त्यागी गई स्त्रियों का जीवन चल जाएगा।

अकेलेपन और अपमान की उस भावना का क्या, जो इन स्त्रियों को झेलनी पड़ेगी। त्यागना या रिजेक्शन एक ऐसी भावना होती है, जो पल-पल सताती है। आज भी बहुत से पुरुषों के मुंह से ये शब्द आसानी से निकलते हैं कि या तो ये कर, वर्ना तुझे छोड़ दूंगा। जैसे कि किसी स्त्री को छोड़ना उसका मौलिक अधिकार हो। ऐसी रील्स से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कई लोगों को इस बात को बहुत अहंकारपूर्वक कहते भी सुना है कि हां मैं किसी और के साथ रहता हूं। रिलेशनशिप में भी हूं, लेकिन जाकर मेरी पत्नी से पूछो कि क्या उसे किसी तरह की तकलीफ होने देता हूं, पैसे, टके, घर, बार आदि की। बाहर क्या करता हूं, इससे उसे क्या मतलब। इस तरह की वाक्यावली दरअसल स्त्री को यही बताने के लिए होती है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, है आज भी दोयम दर्जे की नागरिक।

मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में बयान दिया था कि मुसलमानों के मुकाबले हिंदू और सिख पुरुष दो पत्नियां अधिक रखते हैं। सीताराम येचुरी ने तो पूरी किताब ही लिखी थी। इनके विचारों से हम सहमत न हों, लेकिन अय्यर या येचुरी ने जब यह लिखा, तो इसका मतलब यह भी है कि समाज में एक से अधिक पत्नियां या सम्बंध रखने में बहुत से पुरुष आज भी यकीन करते हैं। भले ही समाज या कानून की नजर में इसे अच्छा न माना जाता हो। कई स्त्रियां भी इन दिनों ऐसा करती पाई जाती हैं, लेकिन उनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है, इसीलिए वे खबर भी बनती हैं।

यह भी लगता है कि अब जब अदालत ने पुरुष के शादीशुदा होने पर भी लिव-इन में रहकर दूसरे सम्बंध को रखने की अनुमति दे दी है, तो ऐसे सम्बंधों को बढ़ने से कैसे रोका जा सकेगा।

यह लेखिका बहुत-सी ऐसी साइट्स को देखती हैं जहां स्त्रियां किसी कानून विशेषज्ञ या काउंसलर तक पहुंच के अभाव में, अपनी समस्याओं को लिखती हैं और सहायता मांगती हैं। यदि यहां सौ स्त्रियां हैं, तो उनमें से कम से कम पचानवे की समस्याएं पति को लेकर हैं। उनमें से भी बहुतों की मुसीबत पति की उपेक्षा और दूसरी स्त्री या अनेक स्त्रियों से सम्बंधों को लेकर है।

जब अदालत का यह फैसला आया तो इन्हीं स्त्रियों के बारे में सोचने लगी। अब तक तो इन्हें लगता था कि ऐसे प्रसंगों में कानून उनकी मदद करेगा, लेकिन यह फैसला तो एक तरह से पत्नी को सताने वाले पुरुषों को और ताकत देगा। इस इक्कीसवीं सदी के पच्चीस साल बाद इस तरह की बातें आश्चर्य और दुःख में जरूर डालती हैं। जो माता-पिता न जाने कितने संसाधन लगाकर अपनी बेटियों को पालते हैं, उन्हें पढ़ाते, लिखाते हैं, उनका विवाह करते हैं, उनकी अच्छी गृहस्थी के सपने देखते हैं, यदि वही लड़की इस तरह से जीवन के थपेड़ों को सहने के लिए पति और कानून द्वारा अकेली छोड़ दी जाएगी, तो इन माता-पिता का क्या होगा। यह लड़की या स्त्री कहां जाएगी। कौन इसे सहारा देगा। क्या सिर्फ मुआवजे के भरोसे पूरा जीवन कट सकेगा।

बीसवीं सदी ने स्त्रियों की समस्या को जिस मानवीयता से देखा था, उनकी बढ़ोतरी के लिए लोकतांत्रिक माध्यमों से जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, क्या यह इक्कीसवीं सदी उन सबको सिर के बल खड़ा कर रही है। एक तरफ संसद में स्त्रियों के लिए तैंतीस प्रतिशत रिजर्वेशन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर कानून द्वारा उन्हें अकेला छोड़ा जा रहा है। माननीय न्यायालय से अपील है कि कम से कम इस फैसले पर दोबारा विचार करे।

प्रेरणा

खामोशी के बीच मां की अंतिम अधूरी पुकार

बीस दिन कभी इतने लंबे नहीं लगे थे जितने शर्मा जी को इन दिनों में लगे। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर शुरू होता और हर रात एक अधूरी निराशा के साथ खत्म हो जाता। उनकी मां कोमा में थीं। जब उन्हें पहली बार अस्पताल लाया गया था, तब डॉक्टरों के शब्दों में भरोसा था, मशीनों की आवाज़ में उम्मीद थी और परिवार की आंखों में विश्वास। हर कोई सोच रहा था कि इलाज होगा, दवाइयां असर करेंगी और मां एक दिन फिर आंखें खोलकर सबको पुकारेंगी। लेकिन समय के साथ वह भरोसा धीरे-धीरे टूटने लगा। डॉक्टरों की भाषा बदल गई, उनकी नजरों में एक चुप्पी उतर आई। अंत में उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया—अब इन्हें घर ले जाइए, जितनी सेवा हो सके, अपने बीच रहकर कीजिए। यह सुनना किसी झटके से कम नहीं था। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच जो उम्मीदें बची थीं, वे भी मानो वहीं रह गईं। एम्बुलेंस आई। मां को सावधानी से स्ट्रेचर पर लिटाया गया। शर्मा जी ने झुककर उनका चेहरा देखा। वह चेहरा, जो कभी हर भाव को खुलकर जीता था, आज एक गहरी शांति में डूबा हुआ था। उस शांति में एक दूरी थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने धीरे से मां का हाथ छुआ, जैसे यह यकीन करने के लिए कि वे अभी भी उनके साथ हैं।

घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। वही पुराना कमरा, जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज गंभीर हो गया था। खिड़की से आती हल्की धूप मां के माथे को छू रही थी, जैसे प्रकृति खुद उन्हें स्नेह दे रही हो। दीवार पर टंगी पिता जी की तस्वीर सब कुछ चुपचाप देख रही थी, जैसे वह भी इस पल के साक्षी हों। सरला चुपचाप मां के पास बैठ गईं। उन्होंने मां का हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा—“मां, हम आपको घर ले आए हैं।” यह वाक्य जैसे एक भरोसा था कि अब आप अपने लोगों के बीच हैं, अपने घर में हैं।

अब घर की दिनचर्या बदल चुकी थी। हर काम मां के इर्द-गिर्द घूमने लगा। समय पर दवा देना, शरीर की सफाई करना, बिस्तर बदलना और सबसे जरूरी—उनसे बातें करते रहना। यह बातचीत भले ही एकतरफा थी, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। शर्मा जी अक्सर मां के पास बैठ जाते और पुराने दिनों की बातें करने लगते। “मां, याद है जब मैं छोटा था और स्कूल से रोता हुआ आया था, आपने कैसे मुझे चुप कराया था?” उनकी आवाज में हल्की मुस्कान होती, लेकिन आंखों में नमी साफ दिखती।

रातें सबसे कठिन थीं। जब पूरा घर सो जाता, तब सन्नाटा और गहरा हो जाता। शर्मा जी की नींद जैसे उनसे रूठ गई थी। वे मां के पास बैठकर किताब खोल लेते, लेकिन पढ़ने से ज्यादा उनका ध्यान मां की सांसों पर रहता। हर छोटी-सी हरकत उन्हें उम्मीद देती। कभी लगता कि पलकें हिली हैं, कभी लगता कि उंगलियां कांपी हैं। हर बार उनका दिल धड़क उठता—“मां?” लेकिन फिर सब वैसा ही शांत हो जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सच है या उनका मन उन्हें धोखा दे रहा है। एक दिन वह मां के बाल संवार रहे थे। बहुत धीरे-धीरे, जैसे कोई कीमती चीज संभाल रहे हों। तभी उन्हें अपना बचपन याद आया। जब वे बीमार पड़ते थे, मां पूरी रात जागकर उनकी सेवा करती थीं। उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखती थीं, दवा देती थीं और हर पल उनका ध्यान रखती थीं। उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भूमिकाएं बदल जाएंगी। उन्होंने मां का हाथ थाम लिया और धीमे स्वर में कहा—“मां, अब मेरी बारी है।” उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी।

उसी क्षण उन्हें लगा कि मां की उंगली में हल्की-सी हरकत हुई है। वे चौंक गए। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर दोबारा महसूस करने की कोशिश की। शायद यह भ्रम था, लेकिन उस भ्रम ने उनके भीतर एक नई उम्मीद जगा दी। उन्हें लगने लगा कि मां सब कुछ महसूस कर रही हैं, बस जवाब नहीं दे पा रही हैं। इस विश्वास ने उन्हें और मजबूत बना दिया।

दिन बीतते गए। हफ्ते महीनों में बदल गए। मां की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन घर के लोगों के दिलों में बहुत कुछ बदल चुका था। वे धीरे-धीरे उस सच्चाई को स्वीकार करने लगे थे, जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। फिर भी, कहीं न कहीं एक उम्मीद बाकी थी।

एक रात अचानक बिजली चली गई। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां कांप रही थीं और घर के अंदर अंधेरा छा गया था। शर्मा जी ने मोमबत्ती जलाई और मां के कमरे में पहुंचे। उस हल्की रोशनी में सब कुछ अलग लग रहा था। उन्होंने मां का हाथ थामा। उसी क्षण उन्हें साफ महसूस हुआ—मां ने उनकी उंगली पकड़ ली है। उनकी सांस जैसे रुक गई। “मां?” उनकी आवाज कांप रही थी। इस बार यह कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने ध्यान से देखा—मां की पलकों में हल्की-सी हरकत हुई। उन्होंने मोमबत्ती को थोड़ा और पास किया। मां के होंठ हिले, जैसे कोई शब्द बनने की कोशिश कर रहा हो।

शर्मा जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। “मां, मैं यहीं हूं कुछ कहना चाहती हो?” उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी पल मां की आंखों के कोने से एक बूंद आंसू बह निकली। यह आंसू जैसे उनके अंदर छिपी हर भावना को बाहर ले आया।

उन्होंने तुरंत सरला को आवाज दी। वह दौड़ती हुई आई। शर्मा जी ने धीरे से कहा—“इन्होंने मेरी उंगली पकड़ी” दोनों उस पल को थाम लेना चाहते थे। तभी मां की सांसें थोड़ी तेज हुईं। उनके होंठों से एक बहुत हल्की आवाज निकली—“स्स्ससर”

बस इतना ही। शब्द अधूरा था, लेकिन भाव पूरा था। शायद वह सरला को बुला रही थीं, शायद कुछ कहना चाहती थीं, या शायद यह उनका अंतिम विदा था। इसके बाद सब शांत हो गया। कमरे में एक गहरी खामोशी फैल गई, जिसमें बहुत कुछ कहा जा चुका था।

सरला रो पड़ी। “मेरा नाम भी पूरा नहीं बोल पाईं” उसकी सिसकियों में दर्द था। लेकिन उस अधूरे शब्द में भी एक अपनापन था, जो हमेशा उनके दिल में रहेगा।

शर्मा जी मां के पास बैठे रहे। अब उनके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति थी। उन्हें किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जाते-जाते मां ने उनका हाथ थाम लिया था। वह स्पर्श ही उनका अंतिम संवाद था—एक अधूरी आवाज, लेकिन एक पूरा विदा।

युद्ध के तूफान में बिजनेस की कश्ती

आज का वैश्विक व्यापार एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां अनिश्चितता केवल एक शब्द नहीं बल्कि वास्तविकता बन चुकी है। एक दशक पहले तक जिन परिस्थितियों को अपवाद माना जाता था, आज वे सामान्य बनती जा रही हैं। युद्ध, क्षेत्रीय संघर्ष, राजनीतिक तनाव और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरण अब केवल कूटनीतिक चर्चाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सीधे तौर पर व्यापार के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं। इसका असर केवल बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे और मध्यम व्यवसाय भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। व्यापार की लागत, आपूर्ति की समयसीमा और रणनीतिक निर्णय अब बाहरी परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित हो रहे हैं। आज जोखिम की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। पहले व्यवसाय किसी एक देश, बाजार या क्षेत्र से जुड़े जोखिमों का आकलन करते थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली हलचल का प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। यह ‘रिपल इफेक्ट’ इतना तेज और व्यापक है कि एक छोटे से व्यवधान से भी पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, किसी एक समुद्री मार्ग में रुकावट आने से न केवल उस क्षेत्र का व्यापार प्रभावित होता है, बल्कि उससे जुड़े कई देशों के उत्पादन और वितरण पर भी असर पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हो रहे बदलाव इस स्थिति को और स्पष्ट करते हैं। व्यापारिक मार्गों में परिवर्तन, परिवहन में देरी और बढ़ती लागत अब आम बात हो गई है। कंपनियों को अपने उत्पादों को समय पर पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश करनी पड़ रही है, जो अक्सर अधिक महंगे और जटिल होते हैं। इसके साथ ही, डिजिटल युग में साइबर खतरों का बढ़ता दायरा एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है। डेटा चोरी, सिस्टम हैकिंग और ऑनलाइन हमलों ने व्यवसायों के लिए जोखिम का एक नया आयाम जोड़ दिया है। इन परिस्थितियों में भविष्य का सटीक अनुमान लगाना लगभग असंभव हो गया है। ऐसे समय में व्यवसायों के लिए केवल प्रतिक्रिया देने वाली रणनीति पर्याप्त नहीं है। अब आवश्यकता है एक ऐसी सोच विकसित करने की, जो संभावित जोखिमों को पहले से पहचान सके और उनके लिए तैयारी कर सके। यह बदलाव केवल नीतियों में नहीं, बल्कि मानसिकता में भी होना चाहिए। कंपनियों को यह समझना होगा कि जोखिम प्रबंधन अब एक पूरक कार्य नहीं, बल्कि उनके संचालन का अभिन्न हिस्सा है। किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा खतरा एक ही स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता है। चाहे वह कच्चे माल का सप्लायर हो, कोई विशेष देश हो या कोई निश्चित परिवहन मार्ग—यदि उस एक स्रोत में कोई बाधा आती है, तो पूरा व्यवसाय ठप हो सकता है। इसलिए आज के दौर में विविधता अपनाना अनिवार्य हो गया है। कंपनियों को अपने सप्लायर नेटवर्क को विस्तारित करना चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों में अपने संसाधनों का वितरण करना चाहिए और वैकल्पिक लॉजिस्टिक मार्गों को तैयार रखना चाहिए। यह रणनीति न केवल जोखिम को कम करती है, बल्कि संकट के समय व्यवसाय को स्थिर बनाए रखने में भी मदद करती है। इसके साथ ही, कंटिंजेंसी प्लानिंग को केवल कागजों तक सीमित रखना अब पर्याप्त नहीं है। इसे व्यवहार में लागू करना और समय-समय पर उसका परीक्षण करना आवश्यक है। व्यवसायों को विभिन्न संभावित परिस्थितियों के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए—जैसे आपूर्ति में बाधा, बाजार में गिरावट या तकनीकी विफलता। इस प्रकार की तैयारी संकट के समय त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में सहायक होती है। जहां परिचालन रणनीतियां व्यवसाय की नींव को मजबूत करती हैं, वहीं बीमा उसे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। अनिश्चितता के इस दौर में बीमा केवल संपत्ति की रक्षा का साधन नहीं रहा, बल्कि यह व्यापार की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। जब कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, तो बीमा कंपनियों को वित्तीय सहारा देता है, जिससे वे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से भटके बिना आगे बढ़ सकती हैं।

व्यापार के विस्तार के साथ-साथ विशेष बीमा समाधानों की आवश्यकता भी बढ़ी है। राजनीतिक और युद्ध से जुड़े जोखिमों के लिए विशेष बीमा अब अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि ये जोखिम अब केवल संघर्ष क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहे। इसी तरह, प्रॉपर्टी और बिजनेस इंटरप्शन बीमा का दायरा भी विस्तारित हुआ है, जिसमें अब ऐसे कवर शामिल हैं जो सप्लायर या अन्य बाहरी कारणों से होने वाले नुकसान को भी कवर करते हैं। इससे कंपनियों को अप्रत्यक्ष नुकसान से भी सुरक्षा मिलती है। समुद्री मार्गों में बढ़ती अनिश्चितता के कारण मरीन और कार्गो बीमा का महत्व भी काफी बढ़ गया है। जब व्यापारिक जहाजों को नए और लंबे रास्तों से गुजरना पड़ता है, तो जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में व्यापक बीमा कवरेज कंपनियों को संभावित वित्तीय नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार, साइबर खतरों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए साइबर बीमा आधुनिक व्यवसायों के लिए अनिवार्य बनता जा रहा है। यह न केवल आर्थिक नुकसान की भरपाई करता है, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में भी सहायक होता है। अंततः, किसी भी संगठन की सफलता केवल उसके संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी सोच और तैयारी पर भी निर्भर करती है। जो कंपनियां जोखिम प्रबंधन को एक औपचारिकता के रूप में देखती हैं, वे अक्सर संकट के समय कमजोर पड़ जाती हैं। इसके विपरीत, जो संगठन इसे अपनी रणनीति का मुख्य हिस्सा बनाते हैं, वे न केवल संकट का सामना करते हैं, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत बनकर उभरते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है। ऐसे में जो व्यवसाय समय रहते अपने आप को ढाल लेते हैं, वही भविष्य में टिके रह पाते हैं। सही योजना, विविधता, और मजबूत जोखिम प्रबंधन के साथ ही कंपनियां न केवल अपने वर्तमान को सुरक्षित कर सकती हैं, बल्कि एक अनिश्चित भविष्य के लिए भी खुद को तैयार कर सकती हैं। यही दूरदृष्टि और तैयारी उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे बनाए रखेगी।

अभियान

हनुमान जयंती पर चालीसा पाठ के अचूक नियम और प्रभाव

चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन पवनपुत्र हनुमान का जन्म हुआ माना जाता है। यही कारण है कि हनुमान जयंती को पूरे देश में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 में भी यह पर्व 02 अप्रैल को मनाया गया, जहां मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। भक्तजन सुबह से ही मंदिरों में उमड़ पड़े और अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा और जाप में लीन रहे। इस अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह न केवल भगवान हनुमान की स्तुति है, बल्कि यह एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति के जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।

हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, और इसमें 40 चौपाइयों के माध्यम से हनुमान जी के गुणों, पराक्रम और भक्ति का वर्णन किया गया है। यह पाठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का एक सशक्त माध्यम है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से भय, नकारात्मकता और बाधाएं दूर होने लगती हैं। यही कारण है कि इसे संकटमोचन स्तोत्र भी कहा जाता है।

हनुमान जयंती के दिन इस पाठ का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन यदि विधिपूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ चालीसा का पाठ किया जाए, तो इसका फल कई गुना अधिक मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन हनुमान जी अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी स्वीकार करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि इस दिन लाखों लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और पूरे दिन हनुमान जी का स्मरण करते हैं।

हालांकि, केवल पाठ कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए कुछ विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है। सबसे पहला नियम है शुद्धता। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो शरीर और मन दोनों की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके साफ वस्त्र पहनना, शांत वातावरण में बैठना और मन को एकाग्र करना इस साधना की शुरुआत के लिए जरूरी है। यदि मन विचलित होगा, तो पाठ का पूरा प्रभाव नहीं मिल पाएगा।

दूसरा महत्वपूर्ण नियम है सात्विक जीवनशैली। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन और संयमित जीवनशैली से शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं, जिससे भक्ति में एकाग्रता बनी रहती है। यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। तीसरा नियम है सकारात्मक सोच। चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष जैसे भाव इस साधना को कमजोर कर देते हैं। इसके स्थान पर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का भाव होना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी आस्था के साथ पाठ करता है, तो उसके शब्दों में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उसके जीवन को प्रभावित करती है।

हनुमान चालीसा का पाठ दिन में तीन बार करना विशेष फलदायी माना गया है। प्रातःकाल का पाठ दिन की शुरुआत को शुभ बनाता है, दोपहर का पाठ मन को स्थिर करता है और संध्या का पाठ दिनभर की थकान और तनाव को दूर करता है। यह नियमितता व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और संतुलन लाती है। धीरे-धीरे यह अभ्यास उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इस पाठ का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसे केवल शब्दों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसके अर्थ और भाव को भी समझा जाए। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई एक गहरा संदेश देती है। इसमें हनुमान जी के बल, बुद्धि, विनम्रता और सेवा भावना का वर्णन है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व भी मजबूत और संतुलित बनता है।

वर्तमान समय में जब जीवन भागदौड़ और तनाव से भरा हुआ है, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है। यह व्यक्ति को भय और असुरक्षा की भावना से मुक्त करता है और उसे आत्मविश्वास से भर देता है। यही कारण है कि आज के युवा भी इस साधना की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। साइबर युग में जहां बाहरी खतरों के साथ-साथ मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है, वहां इस प्रकार की आध्यात्मिक साधनाएं व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता प्रदान करती हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी संतुलित करता है। यह उसे कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति देता है।

धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे विशेष सिद्धि प्राप्त होती है और उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। हालांकि, इसका अर्थ केवल संख्या पूरी करना नहीं है, बल्कि हर बार पूरे मन और श्रद्धा के साथ पाठ करना है। जब यह भावना जुड़ जाती है, तब यह साधना एक शक्तिशाली अनुभव बन जाती है।

अंततः, हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य रखना, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना और हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे-धीरे पूर्ण होने लगती हैं।

हनुमान जयंती का यह पावन अवसर हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कार्य में झलकनी चाहिए। यदि हम सही विधि, शुद्ध भावना और नियमित अभ्यास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो न केवल हमारे कष्ट दूर होते हैं, बल्कि हम एक मजबूत, संतुलित और सफल जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। यही इस साधना का वास्तविक उद्देश्य और सबसे बड़ा लाभ है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

कोडिंग से मैनेजमेंट तक का सफर, धवित मेहता बने IIM-B के गोल्ड मेडलिस्ट

आनंद (गुजरात)। जीवन में सफलता केवल एक दिशा में लगातार आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने और अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का परिणाम भी है। गुजरात के आनंद शहर के रहने वाले 27 वर्षीय धवित मेहता की कहानी इसी बात का जीता-जागता उदाहरण है, जिन्होंने कोडिंग की दुनिया से निकलकर मैनेजमेंट की पढ़ाई में ऐसा मुकाम हासिल किया कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान Indian Institute of Management Bangalore में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी पहचान बना ली। इतना ही नहीं, उन्हें संस्थान की प्रतिष्ठित 'वॉल ऑफ फेम' में भी जगह मिली, जो किसी भी छात्र के लिए गर्व का क्षण होता है।

धवित मेहता का सफर गुजरात के आनंद शहर से शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। शुरुआती दिनों से ही उन्हें तकनीक और कोडिंग में गहरी रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपने करियर की दिशा तय करते हुए Indian Institute of Information Technology Allahabad का चयन किया, जो देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में गिना जाता है। यहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डुअल डिग्री, यानी बीटेक और एमटेक, पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपनी तकनीकी दक्षता और विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत किया, जो आगे चलकर उनके करियर की नींव बनी।

साल 2021 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद धवित ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में कदम रखा। कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अमेरिकी क्लाउड कंपनी के साथ की, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्हें दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Microsoft में काम करने का अवसर मिला, जिसने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी। जुलाई 2022 में वह नॉर्वे चले गए, जहां

उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए न केवल अपने कौशल को निखारा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई। करीब दो वर्षों के दौरान उन्हें प्रमोशन भी मिला और उनका करियर स्थिर और सफल दिखाई देने लगा।

लेकिन धवित की सोच केवल एक सुरक्षित करियर तक सीमित नहीं थी। उनके भीतर कुछ नया करने और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने की चाह लगातार बनी रही। इसी दौरान उनकी रुचि फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया की ओर बढ़ने लगी। इस रुचि को गहराई से समझने के लिए उन्होंने अपने व्यस्त प्रोफेशनल जीवन के साथ-साथ CFA Institute के प्रतिष्ठित चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (CFA) प्रोग्राम को भी चुना। बिना किसी कोचिंग के उन्होंने इसके लेवल I और II को पास कर लिया, जो उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास को दर्शाता है।

उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साल 2024 में आया, जब उन्होंने एक साहसिक निर्णय लेते हुए Microsoft Norway की नौकरी छोड़ दी और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए भारत लौट आए। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि एक स्थिर और सफल अंतरराष्ट्रीय करियर को छोड़ना जोखिम भरा कदम माना जाता है। लेकिन धवित ने अपने अंदर की आवाज सुनी और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी।

मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी उन्होंने पहले ही शुरू कर दी थी। साल 2021 में उन्होंने कम तैयारी के बावजूद CAT परीक्षा में 98.5 परसेंटाइल स्कोर किया, जो उनकी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण था। हालांकि, उन्होंने उस समय Indian Institute of Management Indore में दाखिला न लेने का फैसला किया, क्योंकि वह अपने लिए और बेहतर अवसर की तलाश में थे। इसके बाद 2023 में उन्होंने दोबारा CAT परीक्षा दी और इस बार उन्हें देश के कई शीर्ष प्रबंधन संस्थानों से इंटरव्यू कॉल प्राप्त हुए। शुरुआत में उन्हें IIM बैंगलोर में वेटिंग लिस्ट में रखा गया, लेकिन अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें PGP प्रोग्राम में प्रवेश मिल गया।

IIM बैंगलोर में पढ़ाई के दौरान धवित ने न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि अपने बहुआयामी अनुभव और अनुशासित दृष्टिकोण के दम पर खुद को अलग साबित किया। तकनीकी पृष्ठभूमि, अंतरराष्ट्रीय कार्य अनुभव और फाइनेंस की समझ ने उन्हें एक ऐसा छात्र बना दिया, जो हर चुनौती को नए नजरिए से देखता था। यही वजह रही कि उन्होंने अपने बैच में टॉप करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया और संस्थान की 'वॉल ऑफ फेम' में अपना नाम दर्ज कराया। वह आदित्य शाह के बाद IIM बैंगलोर में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे गुजराती बने।

धवित मेहता की कहानी आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो यह दिखाती है कि करियर में बदलाव कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य, मेहनत और सही दिशा में सोचने की क्षमता है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। कोडिंग से मैनेजमेंट तक का उनका यह सफर केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि जोखिम उठाने और अपने सपनों का पीछा करने से ही असली सफलता मिलती है।

चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं और रेवाड़ी संस्कृति पर सवाल उठाए गए

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश में चुनाव का मौसम नजदीक आने के साथ ही सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दल मतदाताओं को लुभाने के लिए विज्ञापन जारी कर रहे हैं। इस दौरान मुफ्त उपहार बांटने का चलन भी बढ़ रहा है। कुछ समय पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये जमा किए थे। इसी तरह पंजाब सरकार ने अब "मुख्यमंत्री मावन-ध्यान सत्कार योजना" को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे। यह 2022 के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया एक बड़ा वादा था। यह वादा अब अगले चुनाव चक्र से एक साल पहले लागू किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राज्य सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को यह "मुफ्त उपहार" दिया है?

कुछ साल पहले, जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने चुनाव से पहले "लाडली बहन" योजना पेश की और भारी बहुमत से जीत हासिल की। तब से, विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने का एक नया फॉर्मूला खोज निकाला है। इसके बाद, महाराष्ट्र से लेकर जहां भी चुनाव होते हैं, सत्ताधारी से लेकर विपक्षी दल तक, सभी तरह-तरह के मुफ्त पैकेज देने लगे हैं और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस 'रेवाड़ी' संस्कृति पर नाराजगी जताई है।

लेकिन राजनीतिक दलों और सरकारों में कोई सुधार नहीं हुआ है। और यह गतिविधि अभी भी जारी है। अब पंजाब भी इसमें शामिल हो गया है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री रेवड़ी संस्कृति की बात करके विपक्ष का मजाक उड़ाते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी ने बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक के चुनावों में रेवड़ी बांटकर सत्ता हासिल की है। कहा जाता है कि अगर मैं करूं तो ठीक है, और अगर दूसरे करें तो बुरा है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए देशभर में सरकारी योजनाओं को जल्दबाजी में लागू करने के तरीके की बार-बार आलोचना की गई है और सवाल उठाए गए हैं। मुफ्त उपहार बांटने का यह चलन सरकारी खजाने पर बोझ डाल रहा है। पिछले महीने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कई राज्य सरकारें पहले से ही कर्ज में डूबी हैं, तो वे मुफ्त उपहार क्यों बांट रही हैं?

यह हमारे लोकतांत्रिक देश की सच्चाई है, जहां मतदाताओं को खरीदा जाता है और सरकारें बनाई जाती हैं, और अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करने वाला वर्ग भी इसकी परवाह नहीं करता, तो बाकी लोगों का क्या?

चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज, गंगोत्री में बढ़ा दर्शन समय, श्रद्धालुओं को बड़ी राहत

देहरादून। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही हैं। हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनने वाली इस यात्रा के लिए इस बार प्रशासन और मंदिर समितियों ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इसी क्रम में Gangotri Dham में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरती और दर्शन के समय में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे इस बार भक्तों को पहले की तुलना में दो घंटे अधिक दर्शन का अवसर मिलेगा।

मंदिर समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, अब श्रद्धालु सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले यह समय दोपहर 2 बजे तक ही सीमित था, जिससे दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस बदलाव को यात्रियों की बढ़ती संख्या और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।

मंदिर समिति के सचिव Suresh Semwal ने बताया कि इस बार यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दर्शन की नई समय सारणी तैयार कर ली गई है, जिससे श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में मदद मिलेगी और अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा।

चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है, जब अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12 बजकर 15 मिनट के शुभ मुहूर्त में खुलेंगे। इसके बाद श्रद्धालु पूरे दिन दर्शन कर सकेंगे। वहीं जो श्रद्धालु देर शाम तक पहुंचते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है—शाम की आरती रात 7:45 बजे समाप्त होने के बाद रात 10 बजे तक दर्शन की अनुमति दी जाएगी।

चारधाम यात्रा के अन्य प्रमुख धामों की बात करें तो Kedarnath Temple के कपाट 22 अप्रैल को सुबह लगभग 8 बजे खोले जाएंगे, जबकि Badrinath Temple के कपाट 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह करीब 6:15 बजे खुलेंगे। हर साल की तरह इस बार भी इन धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। वहीं Hemkund Sahib के कपाट खोलने की तारीख अलग से घोषित की जाएगी, जो सामान्यतः मई माह में होती है।

चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग सहित अन्य जिलों में जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। खासतौर पर होटल, लॉज, रिसॉर्ट और होमस्टे संचालकों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे यात्रा शुरू होने से पहले अपनी दरों को जिला पर्यटन कार्यालय से अनुमोदित कराएं। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली को रोकना और पारदर्शिता बनाए रखना है।

इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा नियंत्रण के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और चिकित्सा टीमों को भी अलर्ट पर रखा जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर: दिल्ली से राजस्थान तक बदला मौसम, कई राज्यों में बारिश-ओलों का अलर्ट

नई दिल्ली। उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और तेज गर्मी के बीच आई बारिश की फुहारों ने लोगों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली-एनसीआर में रविवार सुबह कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और वातावरण सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और दोपहर से शाम के बीच फिर से बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग India Meteorological Department ने 7 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि कई स्थानों पर तेज हवाओं, आंधी और बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है।

दिल्ली में आज अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 8 अप्रैल को भी बारिश के आसार बने रहेंगे, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है और लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिलती रहेगी। हालांकि इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है, जो उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने अचानक रुख बदल लिया है। Uttar Pradesh के कई जिलों में आज बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर और मुजफ्फरनगर समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी

चेतावनी दी है। बीते दिन भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है और किसान चिंतित नजर आ रहे हैं।

वहीं Bihar में भी मौसम यू-टर्न लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल से राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू हो सकती है। राजधानी पटना समेत अन्य क्षेत्रों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। इससे जहां तापमान में गिरावट आएगी, वहीं लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है।

मध्य प्रदेश में मौसम का असर और अधिक तीव्र रूप में देखने को मिल सकता है। Madhya Pradesh के कई जिलों में आज बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नीमच, मुरैना, श्योपुर और मैहर सहित कई इलाकों में ओले गिरने की संभावना है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसके अलावा तेज आंधी और हवाओं के कारण पेड़ों और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंच सकता है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। Rajasthan के कई जिलों में आज और कल बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर और जोधपुर समेत कई शहरों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 7 अप्रैल के लिए कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन किसानों के लिए यह स्थिति चिंता का कारण बन सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जो हिमालयी क्षेत्रों से होते हुए मैदानी इलाकों में सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से न केवल बादल छा रहे हैं, बल्कि नमी बढ़ने के कारण गरज-चमक और आंधी-तूफान की स्थिति भी बन रही है।

इस बीच मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न जाएं, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में अगले दो-तीन दिनों तक मौसम का यह बदला हुआ रूप बना रह सकता है। जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं तेज आंधी, बिजली और ओलावृष्टि ने सतर्क रहने की जरूरत भी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में मौसम के इस उतार-चढ़ाव पर सभी की नजर बनी रहेगी, क्योंकि इसका सीधा असर जनजीवन और कृषि पर पड़ने वाला है।

गैस रिफिलिंग यूनिट में घातक विस्फोट: 4 लोगों की मौत, 8 घायल!

इकाई के पास अप्रूव्ड प्लान, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी द्वारा जारी कंटेंट, एवं संबंधित विभाग द्वारा एक्सप्लोसिव लाइसेंस आदि कंपनी के पास थे या नहीं ?

संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के देमनी विस्तार में शनिवार सुबह करीब 9:15 बजे एक भीषण हादसा सामने आया, जब एक गैस रिफिलिंग यूनिट श्री साई कृपा एंटरप्राइज में जोरदार धमाका हो गया, जिससे पूरा इलाका हिल गया। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि यह यूनिट एक शैक्षणिक परिसर से महज 30 मीटर की दूरी पर स्थित बताई जाती है। अगर यह विस्फोट स्कूल के समय के दौरान हुआ होता, तो यह स्थिति संभावित रूप से बड़े जनहानि का कारण बन सकती थी।

विस्फोट इतना भीषण था कि 4 कर्मचारियों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। आठ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए, दादरा और नगर हवेली के दमकलकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल दल ने आग पर काबू पा लिया।

विस्फोट की घटना के बाद, एक मोबाइल फोरेंसिक वैन घटनास्थल पर पहुंची और टीम के सदस्यों ने विस्फोट के कारण का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दादरा नगर हवेली के समाहर्ता श्री प्रियांक किशोर ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "जांच जारी है और एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है। अगर इकाई/यूनिट अवैध पाया जाता है, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे।"

इस पूरे मामले में उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों के अनुसार बताया जाता है कि कंपनी का आधिकारिक नाम श्री साई कृपा एंटरप्राइज है तथा कंपनी श्री साई कृपा गैसेस के नाम से भी जानी जाती है, उक्त कंपनी के मालिक का नाम गिरीश प्रजापति है, तथा उक्त कंपनी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO, D/A, हाइड्रोजन और भी बहुत कुछ; तरल, थोक या सिलेंडर के रूप में औद्योगिक सप्लाई करती है।

पड़ताल करने पर यह भी पता चला है की केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत वर्ष 2019 तथा वर्ष 2021 में श्री साई कृपा एंटरप्राइज को विभाग द्वारा नोटिस भी जारी हुए है, जिससे यह संकेत मिलता है की उक्त कंपनी की कार्यप्रणाली सरकार से छुपी नहीं थी, परंतु जिस स्थान पर यह कंपनी कार्य कर रही थी उस इकाई के निर्माण संबन्धित स्वीकृति, इकाई का अप्रूव्ड प्लान, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी द्वारा जारी कंसेंट, एवं संबन्धित विभाग द्वारा एक्सप्लोसिव लाइसेंस आदि उस कंपनी के पास थे या नहीं इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभागों द्वारा की जानी शेष है। विशेषज्ञों की राय : औद्योगिक, मेडिकल एवं स्पेशियलिटी गैस (जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि) के निर्माण, भंडारण एवं वितरण का व्यवसाय अत्यंत नियंत्रित एवं उच्च जोखिम श्रेणी में आता है, जिसके लिए उद्यमियों को विभिन्न केंद्रीय एवं स्थानीय सरकारी विभागों से कई अनिवार्य स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं। प्रमुख रूप से पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से गैस सिलेंडर भराई, भंडारण एवं प्रेशर वेसल से संबंधित लाइसेंस, फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत फैक्ट्री लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण समिति से कंसेंट टू एस्टेब्लिश एवं कंसेंट टू ऑपरेट, अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी, स्थानीय प्रशासन से भूमि उपयोग परिवर्तन एवं भवन अनुमति, लीगल मेट्रोलॉजी पंजीकरण, तथा मेडिकल ऑक्सीजन के लिए ड्रग लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त खतरनाक पदार्थों के परिवहन, प्रेशर वेसल स्वीकृति, विद्युत सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों से जुड़े अन्य अनुमोदन भी आवश्यक हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यापक नियामकीय अनुपालन और सुरक्षा मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस भीषण विस्फोट और घटना के बाद पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल फैल गया है। स्थानीय निवासियों में आवासीय और शैक्षणिक परिसर में ऐसे खतरनाक गोदामों की मंजूरी को लेकर कई सवाल और आक्रोश देखने को मिल रहे हैं। तथा आम जनता में यह चर्चा भी है और मांग भी कि स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस मामले की जांच के साथ साथ यह भी पता लगाना चाहिए कि दादरा नगर हवेली एवं दमण-दीव में और कितने निर्माण, इमारतें, इकाइयां है जिनके पास अप्रूव्ड प्लान, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी द्वारा जारी कंटेंट, एवं संबंधित विभागों द्वारा जारी अन्य लाइसेंस एवं स्वीकृति आदि नहीं है, ताकि समय रहते उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सके और उचित संज्ञान लिया जा सके। साथ ही साथ एक बार सभी विभागों को समय समय पर मिली उन सभी शिकायतों पर भी ध्यान देना चाहिए जो लंबे समय से धूल चाट रही है।

सूरत में एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए एजेंटों द्वारा लिए जा रहे अतिरिक्त शुल्कों पर सवाल उठाए गए हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के आरटीओ अधिकारी सूरत को दलालवाड़ी की दुकान समझते प्रतीत होते हैं। क्योंकि अब तक एचएसआरपी नंबर प्लेट बनाने का काम आरटीओ कार्यालय के अंतर्गत आता था। दोपहिया वाहनों के लिए 140 रुपये प्रति जोड़ी और चार पहिया वाहनों के लिए 450 रुपये प्रति जोड़ी की दर से नंबर प्लेट जनता को मिलती थी। अब आरटीओ ने यह काम बंद कर दिया है और एजेंटों को एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट बनाने की अनुमति दे दी है। ऐसा लगता है मानो एजेंट महंगाई से लड़ रहे हों और दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों से क्रमशः 900 रुपये और 1500 रुपये वसूल कर उन्हें लूट रहे हों? फिर सवाल उठता है कि जब सरकार अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से जनता को एचएसआरपी नंबर प्लेट की सरकारी कीमतें बताती है, तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। वाहन चालकों को उन सरकारी विज्ञापनों में

प्रकाशित कीमतों का कोई लाभ नहीं मिलता। मनमानी कीमतें वसूल कर एजेंट सरकार की नाकामी का उदाहरण पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आरटीओ समेत पूरी सरकारी व्यवस्था इस मामले में चुप बैठी है।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि आरटीओ द्वारा जारी आदेश कि दोपहिया वाहन शोरूम में प्रत्येक वाहन पर अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट होनी चाहिए, एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है: क्या आरटीओ और नंबर प्लेट बनाने वाले गांधी वैद्य के सहयोगी की तरह काम नहीं कर रहे हैं?

रेलवे संचार क्रांति की ओर बड़ा कदम, अहमदाबाद-रतलाम मंडलों में 398 करोड़ की ओएफसी परियोजना को मंजूरी

नई दिल्ली, 04 अप्रैल। भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क को आधुनिक, सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद और रतलाम मंडलों में संचार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 398.36 करोड़ रुपये की लागत वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बैकबोन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना न केवल रेलवे की तकनीकी क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य की उन्नत प्रणालियों के लिए भी मजबूत आधार तैयार करेगी।

रेलवे के अनुसार इस परियोजना के तहत 4×48 ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन स्थापित किया जाएगा, जिससे संचार नेटवर्क की गुणवत्ता और गति दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह परियोजना 'भारतीय रेलवे के बाकी बचे मार्गों पर दीर्घकालिक विकास (एलटीई) के संचार बैकबोन के साथ कवच की व्यवस्था (अम्ब्रेला वर्क 2024–25)' के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस व्यापक योजना के तहत 'कार्य कार्यक्रम 2024–25 (पीएच-33)' में कुल 27,693 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जो भारतीय रेलवे के समग्र आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

पश्चिमी रेलवे के लिए भी इस योजना के अंतर्गत 2,800 करोड़ रुपये की लागत से एक सब-अम्ब्रेला वर्क को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अहमदाबाद-रतलाम ओएफसी परियोजना को लागू किया जाएगा। यह दर्शाता है कि रेलवे अपने विभिन्न जोनों में संचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए चरणबद्ध तरीके से बड़े निवेश कर रहा है, ताकि पूरे देश में एक समान और विश्वसनीय संचार व्यवस्था स्थापित की जा सके।

इस परियोजना के तहत कुल 1929 रूट किलोमीटर के दायरे में ओएफसी केबल बिछाई जाएंगी, जिनमें 2×48 फाइबर वाली केबल का उपयोग किया जाएगा। इसमें अहमदाबाद मंडल में 1456 रूट किलोमीटर और रतलाम मंडल में 473 रूट किलोमीटर शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का विस्तार रेलवे के संचार ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। इससे न केवल डेटा ट्रांसमिशन की गति बढ़ेगी, बल्कि संचार प्रणाली की विश्वसनीयता भी पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगी।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस संचार बैकबोन के विस्तार से आधुनिक सिग्नलिंग प्रणालियों को भी मजबूती मिलेगी। खास तौर पर 'कवच' जैसी स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में यह परियोजना अहम भूमिका निभाएगी। 'कवच' सिस्टम का उद्देश्य ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकना और सिग्नलिंग में होने वाली मानवीय त्रुटियों को कम करना है। इसके लिए तेज और निर्बाध डेटा संचार की आवश्यकता होती है, जिसे यह ओएफसी नेटवर्क सुनिश्चित करेगा।

इस परियोजना का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि रेलवे के विभिन्न परिचालन कार्यों में दक्षता बढ़ेगी। यात्री सेवाओं में सुधार के साथ-साथ माल ढुलाई की प्रक्रिया भी अधिक सुगम और तेज हो सकेगी। बेहतर संचार प्रणाली के कारण ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार आएगा और आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देना संभव हो सकेगा। इससे रेलवे की समग्र सेवा गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारतीय रेलवे के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान समय में जब डेटा और संचार किसी भी बड़े नेटवर्क की रीढ़ बन चुके हैं, ऐसे में रेलवे का यह कदम भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इससे न केवल रेलवे के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, बल्कि यात्रियों को भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

इसके अलावा, यह परियोजना देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। बेहतर संचार और तेज माल ढुलाई से उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, जिससे समग्र आर्थिक परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पश्चिमी रेलवे, जो देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क में से एक है, वहां इस तरह की परियोजना का लागू होना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

कुल मिलाकर, अहमदाबाद-रतलाम मंडलों के लिए स्वीकृत यह 398.36 करोड़ रुपये की ओएफसी बैकबोन परियोजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण, सुरक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम है। आने वाले समय में इस परियोजना के पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क पहले से अधिक स्मार्ट, तेज और सुरक्षित बन सकेगा, जिससे देशभर के यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को सीधा लाभ मिलेगा।

ड्रोन के जरिए नशे की बड़ी खेप नाकाम श्रीगंगानगर में 60 करोड़ की हेरोइन जब्त

श्रीगंगानगर (राजस्थान)। भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ड्रोन के जरिए हो रही अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। संयुक्त कार्रवाई में करीब 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे गहन पूछताछ जारी है और कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

यह कार्रवाई सीआईडी, स्थानीय पुलिस और Border Security Force की संयुक्त टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई। अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही इनपुट मिल चुका था कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशे की बड़ी खेप भारतीय क्षेत्र में गिराई जा सकती है। इसी सूचना के आधार पर श्रीकरणपुर क्षेत्र में विशेष रणनीति बनाकर तलाशी अभियान और नाकेबंदी की गई।

अभियान के दौरान रात के समय संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं, जिसमें ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में पैकेट गिराए जाने की पुष्टि हुई। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेरते हुए तलाशी अभियान तेज कर दिया। कुछ ही समय में उन्हें छोटे-छोटे पैकेटों में छिपाई गई लगभग 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। यह खेप बेहद सुनियोजित तरीके से भेजी गई थी, जिससे साफ होता है कि इसके पीछे एक संगठित अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क सक्रिय है।

पुलिस के अनुसार, पैकेट लेने के लिए मौके पर पहुंचे दो युवकों को तुरंत पकड़ लिया गया। बाद में जांच के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया, जिससे कुल चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। प्रारंभिक पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि यह खेप पाकिस्तान स्थित तस्करों द्वारा भेजी गई थी और इसे पंजाब में सप्लाई किया जाना था। यह जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नशे के अंतरराज्यीय नेटवर्क के विस्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है।

जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि यह कार्रवाई समय रहते की गई, जिससे एक बड़ी तस्करी को नाकाम किया जा सका। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के अन्य सदस्य कौन हैं, उनका नेटवर्क किन-किन राज्यों और देशों तक फैला हुआ है और वे किस तरह से ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर नशे की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल नशा तस्करी के लिए तेजी से बढ़ा है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। ड्रोन के जरिए सीमा पार से आसानी से पैकेट गिराना तस्करों के लिए अपेक्षाकृत आसान हो गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हालांकि, इस तरह की सफल कार्रवाई यह दर्शाती है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी नई तकनीकों के साथ खुद को लगातार अपडेट कर रही हैं और इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं।

इस घटना के बाद सीमा क्षेत्र में निगरानी और भी सख्त कर दी गई है। ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, स्थानीय स्तर पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच सके। यह कार्रवाई न केवल एक बड़ी तस्करी को रोकने में सफल रही है, बल्कि इसने यह भी संकेत दिया है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, जो इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की परतें खोल सकते हैं। फिलहाल, गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

स्थापना दिवस पर सूरत में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, घर-घर संपर्क से चुनावी रण की तैयारी तेज

सूरत। गुजरात के सूरत महानगर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 'घर-घर महा संपर्क' अभियान की शुरुआत करते हुए आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। यह अभियान केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और मतदाताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की एक व्यापक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

Bharatiya Janata Party की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और तब से हर वर्ष यह दिन पार्टी के लिए आत्ममंथन, संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन का अवसर बनता आया है। इस बार सूरत में इस अवसर को विशेष रूप से चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाया गया है, जहां पार्टी ने जनसंपर्क के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास शुरू किया है।

इस अभियान की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष Jagdishbhai Vishwakarma के निर्देशों के तहत की गई, जबकि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री C. R. Patil के मार्गदर्शन और सूरत महानगर अध्यक्ष Paresh Patel के नेतृत्व में इसे जमीन पर उतारा गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक सभी ने इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा इस बार चुनावी मुकाबले को लेकर पूरी तरह तैयार है।

अभियान के दौरान सूरत के सभी वार्डों में कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। यह सीधा संवाद पार्टी को मतदाताओं की नब्ज समझने में मदद करेगा, साथ ही स्थानीय मुद्दों को पहचानने और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाने का अवसर भी देगा। इस अभियान में सांसदों, विधायकों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे और अधिक प्रभावी बना दिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के व्यापक जनसंपर्क अभियान चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इससे पार्टी न केवल अपनी नीतियों और योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचा पाती है, बल्कि मतदाताओं के बीच विश्वास और जुड़ाव भी मजबूत होता है। सूरत जैसे बड़े और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में इस तरह की गतिविधियां चुनाव परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकती हैं।

स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अप्रैल को प्रत्येक वार्ड में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं और आम जनता को भाजपा के इतिहास, उसकी विचारधारा, संगठनात्मक मूल्यों और अनुशासन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसका उद्देश्य न केवल कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना है, बल्कि नई पीढ़ी को भी पार्टी के सिद्धांतों से जोड़ना है।

इस अभियान के जरिए भाजपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह केवल चुनाव के समय ही सक्रिय नहीं होती, बल्कि लगातार जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों को समझने और समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और हर मतदाता तक पहुंच बनाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

सूरत में चल रहा यह 'घर-घर महा संपर्क' अभियान आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भाजपा की तैयारियों का स्पष्ट संकेत है। पार्टी ने जिस तरह से अपने पूरे संगठन को इस अभियान में झोंक दिया है, उससे यह साफ है कि वह किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस अभियान का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सूरत की सियासत में हलचल तेज हो गई है और चुनावी माहौल पूरी तरह सक्रिय हो चुका है।

एक ही दिन में उजड़ा पूरा परिवार, झुंझुनू में दर्दनाक दोहरी आत्महत्या से सनसनी

झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है, जहां एक मामूली वैवाहिक विवाद ने कुछ ही घंटों के भीतर हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। पदमपुरा गांव में हुई इस दर्दनाक घटना में पहले पत्नी ने आत्महत्या कर ली और उसकी खबर मिलते ही सदमे में पति ने भी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इस दोहरी आत्महत्या ने न केवल दोनों परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में रिश्तों की संवेदनशीलता और मानसिक दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, 25 वर्षीय सचिन दूधवाल, जो जयपुर में मजदूरी करता था, दो दिन पहले ही अपने एक साल के बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए गांव आया था। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह खुशी इतनी जल्दी मातम में बदल जाएगी। शनिवार सुबह सचिन और उसकी पत्नी भारती (23) के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार के बुजुर्गों को बीच-बचाव करना पड़ा। स्थिति को शांत करने के लिए सचिन के पिता ने उसे वापस जयपुर जाने के लिए कह दिया, ताकि माहौल ठंडा हो सके।

सचिन के गांव से निकलने के बाद घटनाओं ने अचानक भयावह मोड़ ले लिया। घर में मौजूद भारती ने अपने कमरे में जाकर फंदा लगा लिया। जब उसके भाई और चाचा उसे समझाने के लिए कमरे में पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भारती का

शव पंखे से लटका हुआ था। यह खबर पूरे परिवार में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते घर में कोहराम मच गया। उधर, सचिन जयपुर के लिए रास्ते में था, तभी उसे फोन पर पत्नी की आत्महत्या की खबर मिली। इस खबर ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और नवलगढ़ के दुर्जनपुरा के पास पहुंचकर उसने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और शरीर के अंग तक अलग हो गए। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।

सबसे मार्मिक पहलू यह है कि आत्महत्या करने से कुछ ही मिनट पहले सचिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक संदेश पोस्ट किया था। उसमें उसने लिखा था— "कोणी रह सकूं तेरे बिना, आ रहा हूं"। यह संदेश अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे पढ़कर भावुक हो रहे हैं। यह पोस्ट इस बात का संकेत देता है कि वह अपनी पत्नी की मौत के सदमे को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और उसी के पीछे जाने का निर्णय ले लिया। घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जिसने मामले को और जटिल बना दिया है। सचिन के पिता सुभाष का कहना है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी और भारती अपने पीहर जाने की जिद कर रही थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। उनका मानना है कि यह घटना अचानक हुए तनाव का परिणाम है।

वहीं, भारती के पिता ओमप्रकाश खारिया ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी एक गोल्ड मेडलिस्ट धावक थी और मानसिक रूप से बेहद मजबूत थी, वह इतनी कमजोर नहीं थी कि आत्महत्या जैसा कदम उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारती को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था और उससे गहने व पैसे लाने के लिए दबाव बनाया जाता था। इन आरोपों ने मामले को एक नई दिशा दे दी है और पुलिस अब हर पहलू से जांच में जुट गई है।

सुल्ताना थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवाया है। थानाधिकारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह मामला केवल पारिवारिक विवाद का परिणाम है या इसके पीछे कोई और कारण भी छिपा है। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जिस घर में दो दिन पहले बच्चे का जन्मदिन मनाया गया था, आज वहीं मातम पसरा हुआ है। एक मासूम बच्चा अब अपने माता-पिता दोनों को खो चुका है और परिवार के सामने भविष्य की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

ई-कॉमर्स की मनमानी पर सख्ती की मांग सूरत से उठा खुदरा व्यापार बचाने का स्वर

सूरत। देश में तेजी से फैलते ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के बीच पारंपरिक खुदरा व्यापारियों की चिंताओं ने अब एक संगठित स्वर लेना शुरू कर दिया है। सूरत से उठी इस आवाज ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस को तेज कर दिया है, जहां व्यापारिक संगठनों ने ई-कॉमर्स कंपनियों की कथित मनमानी और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर सांसद और Confederation of All India Traders के राष्ट्रीय महामंत्री Praveen Khandelwal ने सरकार से कड़े और पारदर्शी नियम लागू करने की अपील की है, ताकि देश के करोड़ों छोटे और मध्यम व्यापारियों के हितों की रक्षा की जा सके।

खंडेलवाल ने कहा कि देश में ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियां जिस तरह से विस्तार ले रही हैं, उसने पारंपरिक व्यापारिक ढांचे के सामने अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर दी है। उनका कहना है कि विदेशी पूंजी से संचालित कुछ बड़ी कंपनियां बाजार में असंतुलन पैदा कर रही हैं, जिससे छोटे दुकानदारों के लिए प्रतिस्पर्धा करना बेहद कठिन हो गया है। देश के करीब 9 करोड़ व्यापारी, जो रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ माने जाते हैं, इन बदलावों से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने संसद द्वारा पारित Jan Vishwas Bill 2.0 का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में विश्वास-आधारित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उनके अनुसार, यह विधेयक व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सुधारात्मक कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि ई-कॉमर्स सेक्टर में बढ़ती अनियमितताओं पर भी सख्ती से अंकुश लगाना जरूरी है।

खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि कई ई-कॉमर्स कंपनियां प्रिडेटरी प्राइसिंग और अत्यधिक छूट (डीप डिस्काउंटिंग) जैसी रणनीतियों के जरिए बाजार को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा डार्क पैटर्न्स, मार्केटप्लेस मॉडल के नाम पर इन्वेंट्री आधारित संचालन, चुनिंदा विक्रेताओं को प्राथमिकता देना और डार्क स्टोर्स का तेजी से विस्तार—ये सभी प्रवृत्तियां निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इन तरीकों से ग्राहकों को आकर्षित तो किया जा रहा है, लेकिन लंबे समय में यह पारंपरिक व्यापार को खत्म करने की दिशा में ले जा सकता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण बाजार में ऑफलाइन और ऑनलाइन व्यापार के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। यदि एक पक्ष को अत्यधिक छूट और संसाधनों के बल पर बढ़त मिलती है, तो दूसरा पक्ष धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है, जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह दोनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करे और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए। संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए खंडेलवाल ने राष्ट्रीय रिटेल विकास परिषद के गठन की मांग की। उनका कहना है कि इस परिषद के माध्यम से व्यापारिक समुदाय को नीति निर्माण में उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और जमीनी स्तर की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जब तक व्यापारियों की भागीदारी नीति निर्माण में सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक बनाई गई नीतियां पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाएंगी।

इस मांग को Pramod Bhagat ने भी समर्थन दिया। उनका कहना है कि राष्ट्रीय रिटेल विकास परिषद बनने से नीतियां अधिक व्यावहारिक और वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बन सकेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत तेजी से वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में यह जरूरी है कि विकास समावेशी, निष्पक्ष और संतुलित हो।

व्यापारिक संगठनों का मानना है कि यदि समय रहते ई-कॉमर्स सेक्टर में स्पष्ट और सख्त नियम लागू नहीं किए गए, तो इसका असर देश की आर्थिक संरचना पर पड़ सकता है। छोटे व्यापारियों के बंद होने से न केवल रोजगार पर असर पड़ेगा, बल्कि स्थानीय बाजारों की विविधता और प्रतिस्पर्धा भी खत्म हो सकती है।

सूरत से उठी यह मांग अब राष्ट्रीय बहस का रूप लेती जा रही है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और किस प्रकार से पारंपरिक तथा डिजिटल व्यापार के बीच संतुलन स्थापित करती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि देश का खुदरा व्यापार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां लिए गए फैसले भविष्य की आर्थिक दिशा तय करेंगे।